ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

जलवायू परिवर्तन ने गृहिणी से मजदूर बनाया

रविवारीय, 29 सितंबर-04 अक्टूबर 2019, वर्ष-एक, अंक-8,रांची | हिन्दी साप्ताहिक | R.N.I. No. JHAHIN 00962 | कुल पृष्ठ 4 | मूल्य 2 रूपये

सूचना

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

सीसीएलः हड़ताल के बावजूद 70 प्रतिशत कोल उत्पादन

कोयला क्षेत्र के विभिन्न श्रमिक संघों द्वारा 24 सितम्बर को आहूत हड़ताल के बावजूद सीसीएल का कोयला उत्पादन लगभग 70 प्रतिशत रहा। 24 सितम्बर को 30 से 35 प्रतिशत कर्मियों ने अपना योगदान दिया। कार्य पर अनुपस्थित कर्मियों में लगभग 5 से 7 प्रतिशत कर्मी लंबी अवकाश एवं स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित रहे थे। सीसीएल मुख्यालय सहित सभी कमांड क्षेत्रों में हड़ताल शांतिपूर्ण माहौल में रहा जो श्रमिक संघों के प्रतिनिधिगण एवं सीसीएल कर्मियों की परिपक्वता को दर्शाता है साथ ही उनके कंपनी के प्रति जिम्मेदार रवैये का भी उदाहरण है। सीसीएल में तीनों पालियों में लगभग 84 हजार टन कोयले का उत्पादन हुआ जो इस माह में प्रतिदिन औसत उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत है। दूसरी तरफ लगभग 26 हजार टन कोयला भी प्रेषित किया गया। सीसीएल में वर्तमान में लगभग 40 लाख टन कोयला स्टॉक है ।

वन विभाग ने मिक्सर मशीन किया जप्त।

वन विभाग ने मिक्सर मशीन को जब्त कर लिया है। जब्त मशीन राजवीर कंट्रक्शन कंपनी की है जो पिठौरिया से राय तक का पथ निर्माण कार्य कर रही थी। सूत्रों की माने तो वन विभाग के क्षेत्र में अनधिकृत रूप से कार्य करने के कारण इसे जब्त किया गया। बताते चले कि दो सप्ताह पूर्व दो ट्रैक्टरों को बिना कार्रवाई के वन विभाग ने छोड़ दिया था ।

रांची को भा रही सायकिल की सवारी

रांची : कभी आम भारतीय की सवारी रही सायकिल बीच के कुछ दशकों तक सिर्फ गरीब और मजबूर लोगों की सवारी हो गयी थी। लेकिन हाल में मधुमेह एवं अन्य रोगों, ट्रैफिक जाम , पेट्रोल की बढती कीमतों, शौक एवं सबसे महत्वपूर्ण ट्रैफिक नियमों में सख्ती जैसे कई कारणों ने रांची वासियों ने सायकिल की ओर रूख किया है। हालांकि इसमें ज्यादतर युवा, स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र और फूड डिलिवरी ब्वॉय हैं। अगर कम दूरी के लिये आम आदमी भी सायकिल का उपयोग करने लगे तो, यह हरेक लिहाज से अच्छा होगा। पर्यावरण स्वास्थ्य, ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात के साथ ही ईंधन की फिजुलखर्ची से भी बचा जा सकता है। साथ ही जेब पर भी बहुत कम बोझ पड़ेगा। हालांकि ऐसा होना अभी दूर की कौड़ी लगती है। अगर रांचीवासियों ने सायकिल को खुल कर अपनाया तो यह एक उदाहरण बन सकता है। कुछ महिने पहले झारखंड सरकार ने चार्टर्ड कंपनी से रांची में सायकिल सर्विस देने की एक बेहतरीन योजना की शुरूआत की। शुरूआत के कुछ दिनों की समस्याओं के बाद मोबाइल एप्प आधारित यह सेवा रांची के लिये बेजोड़ साबित हो रही है।

सफल रही चार्टर्ड की सर्विस

कुछ महिनों पहले चार्टर्ड कंपनी की सायकिल सर्विस रांची में शुरू की गयी थी। झारखंड सरकार की रांची में आम लोगों के लिये सायकिल सर्विस शुरू करवाने का यह प्लान कुछ शुरूआती बाधाओं के बाद आज सफल रहा है। चार्टर्ड कंपनी ने रांची के अलावा भोपाल और गुजरात में ऐसी सर्विस पहले से ही चालू कर रखी है।इस सर्विस में आप सब्सक्रिप्शन लेकर रांची में कंपनी के किसी भी स्टैंड से सायकिल लेकर जा सकते हैं जिसका रेंट आनलाइन काटा जाता है।

सुनीता नारायण से लेकर सनी शारद, आरयू मास कॉम के प्राध्यापक, संकर्षण परिपूर्णन ,ज्यां द्रेज सभी सायकिल पर

ऐसा नहीं है कि रांची में सिर्फ,युवा, छात्र या डिलिवरी ब्वॉय ही सायकिल से आना जाना करते हैं। युवा और जाने माने पत्रकार सनी शारद भी अक्सर सायकिल से अपने कार्यालय आते जाते रहे हैं। वहीं पत्रकारिता विभाग के प्राध्यापक संकर्षण परिपूर्णन भी सायकिल से ही मोराबादी कैंपस में कॉलेज आना जाना करते हैं।अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज तो अक्सर ही अपने सायकिल से रांची की सड़कों पर दिख जाते हैं। सुबह रांची के मोराबादी मैदान में भी बहुत सारे लोग सायकिल की सवारी करते मिल जायेंगे। लेकिन ये लोग सिर्फ व्यायाम की दृष्टि से सायकिल की सवारी करते हैं। बाद के दिनचर्या में ऐसे लोग बाइक या कार से ही आना जाना करते हैं।

यूरोप में कोई झिझक नहीं

विदेशों में अमीरों का सायकिल से चलना आम बात हैं। वहां कोई इसे उपहास भाव से नही देखता। गुगल के कैंपस में भी सायकिल से आना जाना किया जाता है। नीदरलैंड के राष्ट्रपति अपने दफ्तर जाने के लिये सायकिल का उपयोग करते हैं। विदेशों में ऐसे-ऐसे सायकिल हैं जो बाइक से भी महंगे हैं।

अभी रांची में 60 स्टैंड में 600 सायकिल उपलब्ध करा रहे हैं। और लोगों की बढती जरूरतों को देखते हुये हम अगले एक से डेढ महिने में और 600 सायकिलें मंगवा रहे हैं। रांची में हमारे साायकिल सेवा को अच्छा रिस्पांस मिला है। अब अगले फेज में हम उन जगहों पर भी स्टैंड बना कर सर्विस देंगे जहां अभी यह उपलब्ध नहीं है। जैसे हटिया, बूटी मोड़, बिरसा चौक, धुर्वा और कोकर में। पिस्का मोड़ में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के कारण अभी वहां हम स्टैंड नहीं बना रहे हैं। शुरूआत में लोगों को मोबाइल एप्प की पूरी जानकारी नहीं थी लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है।

शशि रंजन
मैनेजर चार्टर्ड ट्रांसपोर्ट,रांची

यूएन में पीएम के भाषण में पर्यावरण और जल संरक्षण पर जोर

हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिये हैं

प्रधानमंत्री ने कहा

- विश्व की दृष्टि से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग में भारत का योगदान बहुत कम है, लेकिन इससे निबटने में भारत का योगदान सबसे ज्यादा है।
- मैं जब संयुक्तराष्ट्र के इस भवन में आ रहा था, तो इसकी दिवारों पर लिखा देखा कि नो मोर सिंगल यूज प्लास्टिक। हम सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत से खत्म करने का एक अभियान चला रहे हैं।
- आने वाले पांच वर्षों में हम जल संरक्षण को बढावा देंगे और 15 करोड़ घरों को पानी पहुंचायेंगे।
- आज के समय में एक बिखरी हुयी दुनिया किसी के हित में नहीं है। हमें एकजुट होना ही होगा।

पीएम मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवॉर्ड बोले- 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान

पीएम मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से अवार्ड मिला है. पीएम मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवॉर्ड बिल गेट्स ने दिया। पुरस्कार मिलने पर पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मान मेरा नहीं बल्कि उन करोड़ों भारतीयों का है जिन्होंने स्वच्छ भारत के संकल्प को न केवल सिद्ध किया बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढाला भी है. महात्मा गांधी की 150 जन्म जयंती पर मुझे ये अवार्ड दिया जाना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर 130 करोड़ लोगों की जनशक्ति, किसी एक संकल्प को पूरा करने में जुट जाए, तो किसी भी चुनौती पर जीत हासिल की जा सकती है।

प्रशिक्षण अवधि में एवं प्रशिक्षणोपरांत भी मिलेगी प्रतिमाह राशि

राष्ट्रीय गोकुल मिशन से बेरोजगारों को मिलेगा पशु चिकित्सा का प्रशिक्षण

राष्ट्रिय गोकुल मिशन कार्यक्रम के तहत बेरोजगारों को तीन महिने की पशु चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झारखंड स्टेट इंप्लीमेंट एजेंसी (JSIA) जो झारखंड सरकार कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत एक स्वायत संस्था के रूप में कार्य करती है वो भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत होटवार रांची में शिक्षित बेरोजगारों को त्रैमासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम दे रही है। इसमें मुख्य रूप से कृत्रिम गर्भ धारण एवं प्रारंभिक पशु चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम की फंडिंग भारत सरकार कर रही है। प्रशिक्षण में एक बैच में 50-60 प्रशिक्षणार्थी होते हैं जिन्हें प्रशिक्षण के बाद पशु चिकित्सा उपकरण भी प्रदान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पशुओं के नस्ल में सुधार एवं शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार देना है। प्रशिक्षण में एक माह कक्षायें और दो माह तक फिल्ड में कार्य सिखाया जाता है। इस अवधि में आवास एवं भोजन नि:शुल्क दिया जाता है साथ ही प्रतिमाह1500 रूपये मानदेय दिया जाता है। प्रशिक्षण समाप्त होने पर प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा ली जाती है और सफल प्रशिक्षणार्थियों को 35000 का चिकित्सा उपकरण एवं मोटरसाइकिल के लिये 25000 रूपया अनुदान दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थी जब फिल्ड में काम करने लगते हैं तो उन्हें तीन वर्षों तक मानदेय के रूप में प्रथम वर्ष 1500 रू. प्रति माह, दूसरे वर्ष 1200 रू. प्रतिमाह एवं तीसरे वर्ष 800 रू. प्रतिमाह दिया जाता है। इसके अलावा पशु के गर्भधारण के बाद प्रति वत्स 50 रू. दिया जाता है। संस्था को भारत सरकार द्वारा 2000 बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने का दायित्व दिया गया है। ट्रेनिंग के लिये मैट्रिक पास होना अनिवार्य है।

बेरोजगार युवकों के लिये यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत ही रोजगारपरक है।

डॉ.के.के.तिवारी
मुख्य अनुदेशक एवं नोडल पदाधिकारी जेएसआइए

बीएयू द्वारा विकसित तीसी की दो किस्में सेंट्रल सीड चैन में शामिल

रांची: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर),नई दिल्ली के सौजन्य से देशभर में संचालित अखिल भारतीय तीसी एवं कुसुम समन्वित अनुसंधान परियोजना की गत दिनों कानपुर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यसमूह की बैठक में प्रजनक बीज इंडेंट के मामले में बीएयू को बड़ी उपलब्धि मिली है.बैठक में बिरसा कृषि वि-श्वविद्यालय के आनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग द्वारा तीसी फसल के दो विकसित किस्मों दिव्या एवं प्रियम को सेंट्रल सीड चैन में शामिल किया गया है.बीएयू को वर्ष 2019-20 में दिव्या किस्म का 1.6 क्विंटल तथा प्रियम किस्म का 1.5 क्विंटल प्रजनक बीज उत्पादन करने का इंडेंट एवं लक्ष्य दिया गया। बीएयू के तीसी शोध परियोजना प्रभारी डॉ सोहन राम ने बताया कि दस

बीएयू को 3.1 क्विंटल प्रजनक बीज उत्पादन का इंडेंट मिला

वर्षों से अधिक शोध के बाद झारखण्ड राज्य के लिए अधिक उपज देने वाली उपयुक्त दो किस्मों को विकसित किया गया. वर्ष 2016 में तीसी की दिव्या तथा वर्ष 2017 में तीसी की प्रियम किस्म केन्द्रीय फसल किस्म रिलीज़ समिति से अनुसंशित प्रदान है. इन दोनों किस्मों को राष्ट्रीय सीड चैन में शामिल किया गया है. इन दोनों किस्मों के प्रजनक बीज से राष्ट्रीय स्तर पर अन्य केन्द्रों में शोध एवं प्रसार को बढ़ावा दिया जायेगा. देश के कई राज्यों में दोनों किस्मों का प्रदर्शन वैज्ञानिकों ने बेहतर पाया है. जिसे देख बीएयू द्वारा उत्पादित प्रजनक बीज से विभिन्न केन्द्रों द्वारा आधार बीज का उत्पादन किया जायेगा और इस आधार बीज से ही सत्यापित व उन्नत बीज का उत्पादन कर किसानों के बीच उपलब्ध कराया जायेगा.

देश में तीसी के उन्नत बीज की काफी मांग

भारत सरकार को हर वर्ष तीसी के उन्नत बीज का काफी अधिक मांग होता है. तीसी के दानों का प्रयोग तेल निकालने व औषधि निर्माण, तने के रेशे से विभिन्न उत्पाद का निर्माण, इसके खली को गाय के चारे में उपयोग और खली की छोटी गोली का मुर्गी के बच्चे को खिलाने में किया जाता है. इसमें 20 प्रतिशत प्रोटीन, 37 प्रतिशत वसा और 28 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. इसमें मौजूद ओमेगा-3की भरपूर मात्रा कोलेस्ट्रोल, हृदय एवं गठिया रोग में लाभदायक है। शेष पेज 3 पर ...

ग्रेटा इज ग्रेट स्वीडन की स्कूली छात्रा ग्रेटा थुनबर्ग का वो भाषण जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है

विश्व बिरादरी से पूछा कि आप की हिम्मत कैसे हुयी ?

ग्रेटा थुनबर्ग एक स्कूली लड़की जिसने पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन पर एक नई बहस शुरू की। ग्रेटा थुनबर्ग की पहल पर ही दुनियाभर में स्कूली बच्चों ने फ्राइडे फॉर फ्यूचर के तहत प्रदर्शन किए। 16 साल की स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने यूएन की क्लाइमेट एक्शन समिट में भाग लिया। वहां पर उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप दुनियाभर के नेताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी। थुनबर्ग ने इसका आक्रोशित और भावुक होकर जवाब दिया। हालांकि उनके जवाब देने से पहले ही दुनिया के बड़े नेता वहां से निकल गए थे। पढ़िये ग्रेटा ने क्या कहा...

मेरा संदेश है कि हम आपको देख रहे होंगे। यह सब गलत है। मुझे समंदर के पार मेरे स्कूल में होना चाहिए था। लेकिन आप सब मदद के लिए हम छोटे बच्चों के पास आ रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई। आपने अपने खोखले शब्दों से मेरे बचपन को छीन लिया। लेकिन मैं तो फिर भी भाग्यशाली हूं। लोग परेशानी में हैं। लोग मर रहे हैं। पूरा पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है। हम सब एक बड़े विनाश की शुरुआत में हैं। और आप लोग बस पैसे और काल्पनिक आर्थिक विकास की बात करते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई। करीब 30 साल से विज्ञान साफ तौर पर यह बता रहा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि इससे मुंह फेर लें और यहां आकर कहें कि आप बहुत कुछ कर रही हैं।जबकि राजनीति और जो उपाय चाहिए वो इस

जलवायु परिवर्तन पर फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान चलाने वाली ग्रेटा थुनबर्ग ने यूनाइटेड नेशन्स के क्लाइमेट एक्शन समिट में भाषण दिया। ग्रेटा का यह भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

परिदृश्य में कहीं है ही नहीं। आप कहते हैं कि आप हमें सुनते हैं और जरूरत को समझते हैं। मुझे नहीं मतलब कि मैं कितने गुस्से में हूं या कितनी नाराज हूं लेकिन मैं इस पर भरोसा नहीं करती हूं। क्योंकि अगर आपने सच में परिस्थितियों को समझा और फिर भी कुछ नहीं किया तो मैं आपको बुरा मानूंगी। मैं इस पर भरोसा नहीं करती हूं। अगले 10 साल में उत्सर्जन को आधे करने के लक्ष्य से वैश्विक तापमान के 1।5 डिग्री बढ़ने और मानव के नियंत्रण के बाहर वाली आपदाओं के रुकने के बस 50 प्रतिशत संभावना है। 50 प्रतिशत शायद आपको स्वीकार्य होगा। लेकिन इन संख्याओं में अधिकतर पर्यावरणीय प्रतिक्रियाएं और वायु प्रदूषण से होने वाली अतिरिक्त गर्मी को शामिल नहीं किया गया है। हमारी पीढ़ी आपकी खराब तकनीक की वजह से पैदा हुई करोड़ों टन कार्बन डाई ऑक्सा-इड को सांस में ले रही है. यह 50 प्रतिशत संभावना हमें स्वीकार नहीं है। हमें इन परिस्थितियों के साथ जीना होगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई यह सोचने की कि इस जलवायु परिवर्तन को सामान्य तौर पर काम करके ही रोका जा सकता है. आज के हिसाब से चीजें चलीं तो साढ़े आठ साल में ही धरती की कार्बन डाई ऑक्साइड को झेलने की क्षमता खत्म हो जाएगी। आज यहां जो आंकड़े दिए गए हैं या योजनाएं बताई गई हैं इन सबसे कोई समाधान नहीं होगा। ये आंकड़े सुकून देने वाली नहीं हैं। आप लोग इस इन समस्याओं को बताने के लिए परिपक्व हैं। आप हमें खत्म करने की कोशिश में हैं। लेकिन हम युवा लोग इस धोखेबाजी को समझ चुके हैं। अगली पीढ़ी की नजरें आपके ऊपर हैं। अगर आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हम आपको ऐसा नहीं करते रहने देंगे। आज यहां पर हम आपको एक चेतावनी दे रहे हैं। संसार अब जाग रहा है. बदलाव आ गया है। चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें।

आपका धन्यवाद।

दीपक सूद एसोचैम के महासचिव बने

नई दिल्ली: कॉर्पोरेट इंडिया, सरकार और फॉर्च्यून 500 कंपनियों में दो-ढाई दशक के अनुभव के साथ उद्योग नेता दीपक सूद ने 26 सितंबर को एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया(एसोचैम) के महासचिव के रूप में पदभार संभाला ।

दीपक सूद, ने इससे पहले भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम किया था। उन्हें कर्नाटक सरकार के निवेश प्रोत्साहन शाखा, निवेश कर्नाटक फोरम (IKF) के सीईओ के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। उन्होंने फोसेको,(बर्मा कैस्ट्रोल कंपनी), लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी), टोटल फिना एल्फ एंड एबीबी लिमिटेड और एबीबी ग्रुप के लिए कुछ वरिष्ठ पदों पर भी काम कियाहै । दीपक सूद फ्लैगशिप कार्यक्रम 'मेक इन इंडिया' की कोर टीम के हिस्से के रूप में जुड़े हुए हैं। 26 साल से अधिक के अपने कैरियर में, सूद ने विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के विभागों के साथ मिलकर काम किया है, जिनमें वाणिज्य और उद्योग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) शामिल हैं। एसोचैम द्वारा बोर्ड पर दीपक सूद का स्वागत किया गया।

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

संपादकीय

शोर नहीं, ठोस काम की है जरूरत

हाल के कुछ वर्षों में पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढी है। कुछ सालों पहले भारत में पर्यावरण कोई मुद्दा नहीं था। इस पर काम करने वाले जागरूक शख्सियतों को बहुत कम ही लोग जानते थे। आज जब विश्व पर्यावरणीय असंतुलन, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जल संकट से दो चार है, तब आम लोगों की नींद खुली है। अब आम आदमी भी इन मुद्दों पर आगे आ रहा है, एकजुट होकर मुखर बन रहा है। और ऐसा किसी भी देश में हो रहा है। इसका एक उदाहरण है कि कुछ साल पहले पाकिस्तान में तिलोर नाम के पक्षी के शिकार पर वहां की आम जनता में भी आक्रोश था और वो विरोध पर उतर आये थे।

इस सच के बावजूद कि, दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम लोगों में चेतना बढी है अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हम **ग्रेटा थुबंर्ग** की सराहना तो करते हैं, पर उसके जैसा प्रयास हममे कोई नहीं करना चाहता। हम कर्नाटक के 105 साल की भारतीय दादी मां थिमक्का के चार किमी में लगाये सैकड़ो पीपल के वृक्षों की चर्चा तो करते हैं, आश्चर्य व्यक्त करते हैं, पर थिमक्का के एक अंश के बराबर भी वृक्षारोपण का हम प्रयास नहीं करते। पर्यावरण संरक्षण का काम सिर्फ सरकारों के जिम्मे नहीं है और न ही अकेले किसी देश की सरकार इसे संपूर्ण रूप से सफल बना सकती है। इसके लिये तो आम लोगों को भी आगे आना होगा।

अमेरिका में जलवायू परिवर्तन विषय पर प्रधानमंत्री का ये कहना कि ***अब हमें सिर्फ बातें नहीं काम करने की आवश्यकता है*** ।बहुत कुछ जता गया। हकीकत में जलवायू परिवर्तन, प्रदूषण, जंगलों की कटाई, वन्य जीवों के अंधाधुंध शिकार, जल संरक्षण से लेकर प्लास्टिक पर रोक जैसे विषयों पर हम शोर तो खूब करते रहे हैं, पर इसके लिये ठोस कदम कम ही उठाये गये हैं। झारखंड जैसे राज्य में तो प्लास्टिक के कैरी बैग पर रोक सालों से प्रहसन बन कर रह गया है। बार-बार इस पर रोक लगी, पर चार दिन बाद इसका उपयोग फिर धड़ल्ले से होने लगा।

एक छोटा उदाहरण रांची में हरमू नदी का लें। दो सालों से सरकार इस नदी को प्रदूषण मुक्त करके जल को साफ करने के प्रयास में लगी हुयी है, लेकिन आज भी हरमू नदी गंदे नाले के रूप में ही नजर आती है।आखिर कमी कहां रह गयी है? बेशक जनसहयोग यहां महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर जनता ने यह बीड़ा उठा लिया होता कि, हरमू नदी को प्रदूषित नहीं होने देंगे, तो आज इस प्रदूषित नदी का कायाकल्प हो चुका होता। विदेशों में कई जगहों पर पेड़ काटने पर कड़े दंड का प्रवाधान है,और वहीं कुछ ऐसे जुनूनी लोग भी हैं जिन्होंने अकेले ही कई कई एकड़ में जंगल लगा कर उस जगह को आबाद कर दिया है। ऐसे जुनूनी लोग शोर गुल से दूर रहते हैं वो बड़े- बड़े आयोजनों में जाने के बजाय चुपचाप पर्यावरण संरक्षण में लगे रहते हैं। इन सभी बातों के बीच कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिन्होंने वन एवं पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कई देशों में किसी किस्म के निर्माण के लिये बंजर और ऊसर भूमि का प्रावधान है, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं। यहां किसी संस्थान, प्रशासनिक भवन के लिये जगह का चुनाव इस नजरिये से नहीं होता कि, उससे कृषि या वनभूमि का कितना नुकसान होगा? बल्कि सुविधाजनक स्थिति देख कर वहां निर्माण कर दिया जाता है। कुछ साल पहले रांची में लॉ कॉलेज का निर्माण धान के खेती लायक एक विशाल भूखंड पर किया गया। यहां राजनीतिक मुद्दे को छोड़ दें तो पर्यावरण के दृष्टि से इसके किसी अन्य विकल्प पर विचार किया जा सकता था। आज बढती आबादी की जरूरतों के लिये प्रकृति का दोहन ,पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सुख सुविधा के साजो सामान, वाहनों की बढती संख्या और पैसों के लालच में हमारी पृथ्वी को भयंकर नुकसान हो रहा है,अमेजन के जंगलों में लगी आग के बारे में भी कहा जा रहा है कि यह आग दुर्घटना नहीं बल्कि लगायी गयी है, ताकी जंगलों का सफाया हो जाये और उन जगहों पर फैक्ट्रियां लगायीं जा सके। ये स्थिति बहुत भयंकर है और अब अगर हम नहीं चेते, तो भौतिक सुख के सारे साजो सामान ऐसे ही रखे रह जायेंगे और हम बर्बाद होंगे।

क्या पहाड़ों को जरूरत है चौड़ी सड़कों की?

क्या पहाड़ों को जरूरत है चौड़ी सड़कों की? चीन सीमा और चार धामों तक पहुंचने वाली सड़को को उच्चस्तर का बनाया जाना है. लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर आशंकाएं और विवाद भी उभर आए हैं. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी ने कुछ सवाल उठाए है

चीन सीमा और चार धामों तक पहुंचने वाली सड़को को उच्चस्तर का बनाया जाना है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर आशंकाएं और विवाद भी उभर आए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी ने कुछ सवाल उठाए हुए हैं। केंद्र की विशाल ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत करीब 12 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना को अगले साल मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य था लेकिन पिछले दिनों लोकसभा में सरकार ने बताया कि सामरिक महत्व का यह नेटवर्क मार्च 2020 तक ही तैयार हो पाएगा। इसे नए उत्तराखंड का सूचक बताया गया है। तरक्की के सपनों में भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये सड़कें क्या उत्तराखंड के पर्यावरण को दुरुस्त कर देंगी या पलायन की तीव्र दर को रोक देंगी या रोजगार के नए अवसर पैदा कर पाएंगी - इस तरह के बहुत से सवाल आम लोगों से लेकर पर्यावरणवादियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं तक सबके जेहन में हैं। उत्तराखंड में विकास के इस नए 'प्रतिमान' पर चर्चा से पहले कुछ बातें याद दिलाना जरूरी ह। प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से उत्तराखंड देश का छठवां सबसे अमीर राज्य है लेकिन इस आय में वृद्धि का संबंध निर्माण और सर्विस सेक्टर से है जो अधिकांशतः मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित ह। राज्य के 16 हजार से ज्यादा गांव, अब भी विकास को तरस रहे हैं। कहने को सड़कें और बिजली तो कई गांवों तक पहुंच गई हैं लेकिन इनके साथ रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव बना हुआ ह। सार्वजनिक स्वास्थ्य की सबसे निचली इकाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत दयनीय ह। 68 फीसदी केंद्र ही ठीकठाक काम कर पा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की किल्लत है, 83 फीसदी आपातकालीन विशेषज्ञों की कमी से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड, शिशु मृत्यु दर के लिहाज से देश के राज्यों में 18वें नंबर पर है। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के मामले में उत्तराखंड अपने पड़ोसी पहाड़ी राज्य हिमाचल से पीछे है। लोग बड़े पैमाने पर शहरी इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं।

पहाड़ों का रिसॉर्टीकरण

पलायन की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि करीब 13 फीसदी की दर से पहाड़ों की आबादी घट रही है, तो 32 फीसदी की दर से मैदानी इलाकों में आबादी बढ़ रही है। इससे मैदानों पर भी बोझ बढ़ रहा है, शहर फैल तो रहे हैं लेकिन सुविधाएं सिकुड़ रही हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक एक हजार से अधिक गांव बिल्कुल खाली हो चुके हैं और उन्हें भुतहा कहा जाने लगा है। पिछले सात साल के दरम्यान यह आंकड़ा बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। रिवर्स पलायन की बातें तो की जा रही हैं लेकिन इसके सटीक आंकड़े नहीं मिले हैं। पहाड़ों की प्रकट खूबसूरती के भीतर तकलीफों की भी सुनसान घाटियां हैं, वे नहीं दिखतीं। सरकारें भी पहाड़ों के रोमान को भुनाती हैं लेकिन व्यवहारिक तौर पर पर्यटन नीति इतनी आकर्षक नहीं कि पर्यटक खिंचे चले आए। पहाड़ों का बस रिसॉर्टीकरण हो रहा है। 2010 से 2015 के बीच उत्तराखंड में सालाना औसत वृद्धि चार प्रतिशत दर्ज की गई. हिमाचल थोड़ा बेहतर है जहां खेती की सालाना औसत वृद्धि नौ प्रतिशत थी। वहां हॉर्टीकल्चर और पारंपरिक खेती को सरकारी नीतियों का सहारा मिला। लेकिन उत्तराखंड में कृषि के विकास के लिए कोई रणनीति नहीं बनी। रही सही कसर जंगली सुअरों और बंदरों ने पूरी कर दी जो फसल को चौपट कर रहे हैं और खेतों और गांव के पास के जंगलों पर जिनका कब्जा ह। लोग अपने खेतों को बंजर ही छोड़ रहे हैं या अच्छी कीमत मिलते ही बेचने को तैयार हैं। कम बारिश, या असाधारण बारिश से नुकसान, रात के तापमान में असाधारण बढ़ोतरी, बीजों की किल्लत, हल लगाने के लिए बैलों की कमी, पानी की कमी, जंगल की आग आदि कई कारण हैं जिनसे खेती पर असर पड़ा ह। जलवायु परिवर्तन तो एक बड़ा फैक्टर है ही, इतने बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण भी पहाड़ के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को प्रभावित करेगा।

मकसद क्या है?

ऑल वेदर रोड के कुछ स्पष्ट औचित्य हैं: चीन सीमा से जुड़ा होने की वजह से सीमांत इलाकों तक चौड़ी सड़कें, सामरिक और रक्षात्मक जरूरतें और रोजाना के यातायात की बेहतरी। सड़कें अवरुद्ध न हों और आम लोगों या यात्रियों को परेशानी न हो, यह बात भी सही ह। लेकिन इन सामरिक इरादों या सरकारी सदाशयताओं को थोड़ा किनारे रख कर देखें तो जिस बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं, और जमीनें निगली जा रही हैं, वह पहाड़ों की सेहत से तो सीधा सीधा खिलवाड़ माना जाएगा। क्या पहाड़ों के हाइवे, मैदानों के आठ लेन या चार लेन की तरह चौड़े और चमक भरे होने चाहिए? अगर मौजूदा सड़कों की ही अच्छी मरम्मत कर दें, मजबूती से पुश्ते लगा दें, मजबूत पुल बना दें और यातायात के नियमों का सख्ती से पालन कराएं तो क्या दिक्कत है? देखा गया है कि सड़कों के विस्तार से ज्यादा यातायात नियमों की अनदेखी और कानूनों की अवहेलना ही सड़क दुर्घटनाओं और सड़क दुर्दशाओं का कारण बनती हैं। फिर इतना पैसा बहाने का क्या औचित्य? अगर चीन तक रक्षा वाहनों की खेप आसानी से पहुंचाने का मामला है तो यह बात गले नहीं उतरती। निश्चित समयावधि में और यातायात को एक निश्चित अंतराल के लिए नियंत्रित कर, यह काम तो कभी भी किया जा सकता है, और यह होता भी रहा है, तो अचानक यह सामरिकता कैसे याद आ गई। ऑल वेदर चार धाम सड़क परियोजना केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री के धार्मिक स्थलों को भी और सुविधापूर्ण ढंग से जोड़ेगी। लेकिन क्या सुविधा की कोई आखिरी परिभाषा या कोई आखिरी पैमाइश हो सकती है? और वे तो पहले से जुड़े हैं ही। ठीक है थोड़ी तकलीफ रास्तों पर होती है लेकिन क्या पहाड़ी सड़कों पर हम मैदानी हाईवे की तरह हवा से बात करने के लिए आते हैं या सावधानी और सजगता के साथ सफर करते हैं? इन सारे सवालों का जवाब यह परियोजना नहीं देती। उन्हें चौड़ा करने के बजाय उन पर हो रहे यातायात को नियंत्रित किए जाने की जरूरत है। आज गंगोत्री से लेकर बद्रीनाथ तक वाहनों की भीड़ से त्रस्त हैं। डीजल, पेट्रोल के प्रदूषण के अलावा प्लास्टिक ने भी हिमालयी स्थलों को रौंद दिया है।

पहाड़ों से खिलवाड़

एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकार को इस बारे में नोटिस भी दिया है। यह कारण बताओ नोटिस उस याचिका के बाद आया जिसमें बताया गया था कि इस सड़क प्रोजेक्ट के तहत 356 किलोमीटर के वन क्षेत्र में कथित रूप से 25 हजार पेड़ काट डाले गए। एनवायरन्मेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट (ईआईए) को लेकर भी यह परियोजना खामोश है। तीसरी बात, यह प्रोजेक्ट उत्तरकाशी की भागीरथी घाटी के पर्यावरणीय लिहाज से संवेदनशील उस क्षेत्र से भी गुजरेगा जिसे इको सेंसेटिव जोन घोषित किया जा चुका है। चार धाम प्रोजेक्ट के तहत 15 बड़े पुल, 101 छोटे पुल, 3596 पुलिया, 12 बाइपास सड़कें बनाई जाएंगी.इस परियोजना से इतर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलमार्ग परियोजना भी स्वीकृत हो चुकी है जिसमें न सिर्फ बड़े पैमाने पर जंगल कटेंगे, वन्य जीवन प्रभावित होगा और पहाड़ों को काटकर सुरंगें और पुल निकाले जाएंगें। उधर पिथौरागढ़ में विशालकाय पंचेश्वर बांध परियोजना एक अत्यंत नाजुक भूगोल पर पांव पसार चुकी ह। टिहरी बांध पहले से कई देशी विदेशी कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। सरकार तो रोप वे को भी बढ़ावा देने की योजना बना रही है। पहाड़ों में जाने के लिए सुगम साधन बताया जा रहा है। सोचिए कि पहाड़ के विकास के नाम पर उसके साथ ऐसे खेल खेला जा रहा है जैसे वो कोई खिलौना है, जो जब चाहे मोड़ दे जहां चाहे घुमा दें।

विकसित देशों में पक्षियों पर और भी शामत है, उनके प्राकृतिक आवास खत्म होना , प्रदूषण और कीटनाशकों का असर इन्हें खत्म कर रहा है

तीन अरब परिंदे कहां गायब हो गए?

पैसर डोमेस्टिकस यानि गौरेया की तादाद घटने की चर्चा तो होती ही है। इसके अलावा भी विश्व भर में अन्य पक्षियों की तादाद तेजी से घट रही है। अमेरिकी उपमहाद्वीप में तो इनकी संख्या घटने के कई आश्चर्यजनक और दुखद कारण हैं।

उत्तरी अमेरिका के आकाश का अकेलापन और सन्नाटा बढ़ गया है, बीते 50 सालों में अमेरिकी आकाश से करीब 3 अरब परिंदे गायब हो गए हैं।

एक नई रिसर्च में उन चिड़ियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई है जिनकी तादाद लगातार कम होती जा रही है हालांकि यह परिंदे अभी लुप्त नहीं हुए हैं। अमेरिका और कनाडा में 50 साल पहले चिड़ियों की तादाद करीब 10.1 अरब थी जो 29 फीसदी घट कर अब 7.2 अरब रह गई है। गुरुवार को साइंस जर्नल में इस बारे में रिपोर्ट छपी है।

कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के संरक्षण वैज्ञानिक केनेथ रोजेनबर्ग का कहना है, "जरूरत इस बात की है कि लोग अपने आसपास के चिड़ियों पर ध्यान दें। वे धीरे धीरे गायब हो रही हैं। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि यह हमारी आंखों के सामने हो रहा है। मुमकिन है कि हमें पता भी ना चले और बहुत देर हो जाए। रोजेनबर्ग और उनके सहयोगियों ने मौसम के रडार का इस्तेमाल कर चिड़ियों की आबादी के आंकड़े जुटाए हैं। इसके अलावा 1970 से अब तक चिड़ियों पर हुए 13 सर्वेक्षणों और उत्तरी अमेरिका की 529 पक्षी प्रजाति के ट्रेंड के बारे में कंप्युटर मॉडल की भी मदद ली गई है। इनमें सभी प्रजातियां नहीं हैं लेकिन करीब तीन चौथाई प्रजातियां शामिल हैं। जो छूट गई हैं उनमें ज्यादातर दुर्लभ प्रजाति की चिड़िया हैं। रोजेनबर्ग ने बताया कि मौसम रडार का इस्तेमाल नया है यह प्रवासी पक्षियों के झुंड की जानकारी देता है। हर साल कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी की मार्गरेट रुबेगा को लोग फोन कर बताते हैं कि उन्होंने चिड़ियों की तादाद कम होती महसूस की है। यह रिसर्च इस समस्या के बारे में जानकारी देती है। रुबेगा ने ईमेल से दिए जवाब में कहा है, "अगर आप किसी दिन सुबह घर से बाहर निकलें और देखें कि आपके आसपास के सारे घर खाली हो गए हैं, तो आपका अंदाजा सही होगा कि कुछ खतरनाक हो रहा है। हमारे 3 अरब पड़ोसी जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले और एंसेफिलाइटिस जैसी बीमारी फैलाने वाले कीड़ों को खाते थे वो अब चले गए हैं। मेरे ख्याल से हम सब को यह सोचना चाहिए कि यह खतरनाक है। आमतौर पर ज्यादा दिखने वाली और आसानी से पहचानी जाने वाली चिड़ियों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है हालांकि अभी वो लुप्त होने की स्थिति में नहीं आई हैं। घरेलू पक्षी गौरैया पर इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है। इस्टर्न मिडोलार्क और वेस्टर्न मीडोवाक पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। इनकी तादाद करीब तीन चौथाई तक कम हो गई है। सभी चिड़ियों की संख्या कम नहीं हो रही है। जैसे कि ब्लूबर्ड की संख्या बढ़ रही है लेकिन इसकी वजह यह है कि लोग उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रोजेनबर्ग 3 साल की उम्र से ही बर्डवाचर हैं। करीब 60 साल पहले उन्होंने पहली बार चिड़ियों को देखना शुरू किया था। जब वो छोटे थे तब उनके पिता उन्हें न्यूयॉर्क में चिड़ियों को दिखाने ले जाते थे। वहां एक फीडर के पास 200-300 ग्रोसबीक (बड़े चोंच वाली छोटी चिड़िया) दिखती थीं।अब उनका कहना है कि 10 चिड़ियों को देख कर ही लोग खुश हो जाते हैं।रिसर्च में केवल जंगली परिंदों को ही शामिल किया गया है, इसमें मुर्गी या इस तरह के दूसरे घरेलू पक्षी शामिल नहीं है। रोजेनबर्ग की रिसर्च इस बारे में नहीं है कि पक्षी क्यों कम हो रहे हैं लेकिन वो पुरानी रिसर्चों का हवाला दे कर इसके लिए आवास छिनने, बिल्लियों और खिड़कियों को दोषी ठहराते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि आवास का खत्म होना चिड़ियों के कम होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है। 2015 की एक रिसर्च बताती है कि अमेरिका और कनाडा में बिल्लियां हर साल 2.6 अरब चिड़ियों को मार देती हैं। इसके अलावा खिड़कियों से टकरा कर 62.4 करोड़ और कारों से टकरा कर 2.14 करोड़ परिंदे हर साल मारे जाते हैं। सवाल है कि ऐसी स्थिति में लोग इन चिड़ियों को कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए बिल्लियों को घर के अंदर रखना होगा। खिड़कियों का इस्तेमाल इस तरह से करना होगा कि उनमें फंसकर या उनसे टकरा कर चिड़ियों के मरने की आशंका ना रहे। इसके साथ ही कीटनाशकों का खेती में इस्तेमाल बंद करना होगा। इसके अलावा वो कॉफी खरीदी जाए जो जंगल जैसे फार्मों में उगाई जाती है। अगर ऐसा हो सके तो आकाश अकेला नहीं होगा, चिड़ियों की गूंज उसका दिल बहलाती रहेगी।

जलमार्ग से दो डिग्री तामपान कम होगा

विकास और रहन-सहन बेहतर बनाने के नाम पर बड़ी संख्या में शहर आबाद किए जा रहे हैं। लेकिन ये शहर असल में कंक्रीट के जंगल हैं, जहां गाड़ियों से निकलने वाला धुंआ और फ़ैक्ट्रियों में लगने वाली बड़ी मशीनें तापमान बढ़ा रही हैं। लेकिन अब शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधे लगाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।अमरीका के कोलंबिया में तो प्रशासन की ओर से पूरे शहर में ग्रीन कॉरिडोर जलमार्ग बनाए जा रहे हैं।प्रशासन के इस प्रयास से तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने में सहायता मिली है।पर्यावरणविद् मोनिका टर्नर का कहना है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तापमान पांच डिग्री तक कम किया जा सकता है। अब अन्य शहर भी ऐसे विकल्पों पर ध्यान दे रहे हैं।इटली के मिलान शहर के नगर निगम प्रशासन ने वर्ष 2030 तक तीन लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में भी इसी तरह की कोशिशें की जा रही हैं। एयर कंडिशनर का इस्तेमाल माहौल ठंडा रखने के लिए किया जाता है। लेकिन असल में इसकी ठंडक हमें भट्टी में झोंक रही है। अगर एसी का इस्तेमाल बदस्तूर जारी रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब गर्मी के आलम में एयर कंडिशनर भी दम तोड़ देंगे लिहाज़ा समय रहते सभी को गर्मी से लड़ने के लिए पारंपरिक तरीक़ों पर अमल शुरू कर देना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायू परिवर्तन पर हो रहे सम्मेलन में स्पष्ट कहा कि अब सिर्फ बातें करने का नहीं काम करने का वक्त है

चिंतन जलवायू परिवर्तन पर भारत की दमदार आवाज

- जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई में भारत की सहभागिता बहुत अहम, यूएन ने की पीएम मोदी की तारीफ
- भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नेतृत्व जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस के विशष दूत ने भारतीय कंपनियों की सराहना की।

कभी जलवायू परिवर्तन और पर्यावरण संकट जैसे विषयों होने वाली बैठकों में यूरोप और अमेरिका के विकसित देश हर समस्या के लिये विकासशील देशों को जिम्मेवार बता कर पल्ला झाड़ लेते थे। अब ये परिस्थिति बदली है और भारत ने आवाज उठा कर अपनी दमदार उपस्थिति जतायी है

जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में सीडीआरआई की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की जलवायु शिखर सम्मेलन 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस के विशेष दूत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम उठाने के लिए भारत की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु संबंधी मामलों में नेतृत्व जारी रखने की पुनः प्रतिबद्धता जताई है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के विशेष दूत लुइस अल्फोंसो डी अल्बा ने कहा, 'भारत का सहयोग व सहभागिता इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि वह एक बड़ा उत्सर्जक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले ही बिआरित्ज के जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर एक बैठक में गुटेरस को जलवायु संबंधी मामलों और खासकर सौर ऊर्जा के संबंध में नेतृत्व जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई थी।

सौर ऊर्जा बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण पहल है। डी अल्बा ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में एशियाई देशों से मिली प्रतिक्रिया संबंधी एक सवाल का जवाब देते हुए इस दिशा में भारत के नेतृत्व का उदाहरण पेश किया। मोदी ने गुटेरस से मिलने के बाद ट्वीट किया था, 'हमने कई मामलों, खासकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के प्रयासों को मजबूत करने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।

भारतीय कंपनियों की सराहना

संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने भारतीय कंपनियों के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा, 'मैंने हाल में भारत की यात्रा की और सीमेंट उद्योग समेत बड़ी संख्या में अनेक कंपनियों - टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियों के साथ बैठक की। ये उद्योग जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं।' अल्बा ने चीन को संदेश दिया कि उसे 'बेल्ट एंड रोड' पहल में हरियाली पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।संयुक्त राष्ट्र महासचिव जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता लागू करने के लिए उपायों में तेजी लाने के मकसद से 23 सितंबर को शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन में विश्व के 100 से अधिक नेताओं ने भाग लिया। अन्य नेताओं के साथ मोदी ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र युवा जलवायु परिवर्तन कार्रवाई शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा।जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में सीडीआरआई की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में सहायक सचिवालय कार्यालय सहित आपदा प्रबंधन आधारभूत संरचना पर अंतरराष्ट्रीय गठबंधन (सीडीआरआई) की स्थापना का फैसला लिया है। हालांकि इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री ने 13 अगस्त को ही मंजूरी दे दी थी। प्रधानमंत्री ने न्यूयार्क में 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में इसकी शुरुआत की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा यह शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और इससे होने वाली आपदाओं से निपटने के राष्ट्राध्यक्षों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया जाता है।

भारत चीन के बिजली संयंत्रों को होगी पानी की कमी

जलवायु परिवर्तन और नदियों के अत्याधिक दोहन से निकट भविष्य में भारत और चीन जैसे एशियाई देशों को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता इन देशों के पास अपने बिजली संयंत्रों को ठंडा करने के लिए पर्याप्त पानी की कमी होगी।

यह अध्ययन 'एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंसेस' जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें पाया गया है कि ऊर्जा के लिए कोयला जलाकर बिजली पैदा करने वाले मौजूदा या प्रस्तावित संयंत्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका के प्रोफेसर जेफरी बेइलिकी ने कहा, ' जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम बदल रहा है। और मूसलाधार बारिश और सूखा दोनों के मामले बढ़े हैं। और मंगोलिया, दक्षिण पूर्वी देश, भारत और चीन समेत एशिया के विकासशील देशों में यह एक बड़ी समस्या बन सकती है। यह उन देशों के लिए एक समस्या हो सकती है जिन्होंने 2030 तक कोयला से 400 गीगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा हुआ है।

सल्फास नहीं आटे का दिया बचायेगा सुरसी से

बारिश के सीजन के बाद वातावरण में नमी हो जाती है जिस कारण भंडारण किए गए अनाज में सुरसी (ढोरा) हो जाता है। हो सकता है इसको आपके एरिया मे कुछ ओर बोला जाता हो। उसको खत्म करने के लिये हम गेहूँ में सल्फास नामक जहर रखते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। आज आपको बिना जहर डाले हमारे बुजुर्गों वाला नुस्खा बताता हूं। आटे का एक दिया सरसों के तेल का बनाए उसकी बाती ऐसी रखें जो ज्यादा देर तक जलता रहे। दिए को अनाज की टंकी के अंदर रख कर जला दें। उसके बाद टंकी को आटे या किसी ओर के साथ एयर टाइट कर दे जिससे उसके अंदर हवा ना जा सके। जब तक तक टंकी में आक्सीजन रहेगी तब तक दिया जलता रहेगा। उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा। और आक्सीजन के खत्म होते ही सब कीट भी मर जाएंगे। हमे सल्फास नहीं डालना पड़ेगा और 15-20 दिन बाद टंकी खोल कर गेहूँ निकाल सकते हैं।

सीसीएल में 'स्वच्छता ही सेवा' के अंतर्गत कार्यक्रम

रांची :भारत सरकार की मुहिम 'स्वच्छता ही सेवा' के अंतर्गत 25 सितम्बर को मोराबादी एवं कचहरी रोड, रांची में आमजन/दुकानदारों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान सीसीएल टीम द्वारा कागज का स्ट्रो दुकानदारों के बीच वितरित किया गया साथ ही उनसे प्लास्टिक का स्ट्रो लिया गया जिसे बाद में रिसाईकल कर दिया जायेगा। इस अवसर पर सीसीएल सीएसआर विभाग के अधिकारियों द्वारा आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट के दुष्प्रभाव के बारे में अवगत कराया गया और उन्हें जागरूक भी किया गया एवं आमजनों तथा दुकानदारों के बीच स्वच्छता थैला का वितरण किया गया।

जेएसएसपीएस के बच्चों के बीच स्वच्छता कार्यक्रम

रांची:25 सितम्बर को खेल गावं, रांची में झारखंड सरकार एवं सीसीएल की संयुक्त पहल से बच्चों के बीच स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों द्वारा ''एक कदम प्लास्टिक वेस्ट मुक्त भारत की ओर'' पर आधारित नाटक का मंचन किया गया जिसे उपस्थित सभी ने सराहा बच्चों द्वारा स्वच्छता पर आधारित पेंटिग का भी प्रदर्शन किया गया जो काफी सराहनीय था। ज्ञातव्य हो कि सीसीएल द्वारा ''एक कदम प्लास्टिक वेस्ट मुक्त भारत की ओर'' के संदेश के साथ सीसीएल मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में 11 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2019 तक ''स्वच्छता ही सेवा'' सीएमडी, सीसीएल गोपाल सिंह के मार्गदर्शन में मनाया जा रहा है।

सीसीएल में शांतिपूर्ण रही हड़ताल

कोयला क्षेत्र के श्रमिक संघ द्वारा आहूत हड़ताल के बावजूद 30 से 35 प्रतिशत कर्मियों ने आज आपने योगदान दिया सीसीएल में सभी कोयला यूनियनो द्वारा 24 सितम्बर को घोषित हड़ताल शान्तिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रही। सीसीएल में वर्तमान में 36674 कर्मचारी कार्यरत है। सीसीएल कंपनी ने पिछले 5 - 6 वर्षो से प्रत्येक वर्ष कोयला उत्पादन, सहित सामाजिक परिवर्तन एवं समावेशी विकास की मुहिम में कई काम किये है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी सीसीएल कमांड क्षेत्रो में भारी वर्षा के बावजूद अभी तक उत्पादन के सभी मापदंडो जैसे कोयला उत्पादन, ओवर बर्डन रिमूवल, कोयला प्रेषण आदि में सकरात्मक वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2019 -20 में भी सीसीएल वृहद् परिवार सम्मिलित प्रयास से अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर पुनः कीर्तिमान रचने की दिशा में अग्रसर है।

सी.सी.एल. और जेएसडीएमएस के बीच रांची में कौशल विकास के लिये एमओयू

रांची: झारखंड के युवाओं के लिए सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) एवं झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाइटी (जेएसडीएमएस) के साझा प्रयास से कौशल विकास के क्षेत्र में सी.सी.एल. एवं जेएसडीएमएस के बीच सहमति ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित हुए। सीसीएल के ओर से महाप्रबंधक (एचआरडी) एस.के. सिंह एवं इंडस्ट्री लिकंड स्कीलिंग के एमडी श्री के.एन. झा ने हस्ताक्षर किये।इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि सीसीएल के निदेशक (कार्मिक) आर.एस. महापात्र मुख्य प्रबंधक रत्नेश श्रीवास्तव एवं इंडस्ट्री लिकंड स्कीलिंग के सीईओ अमर झा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सीसीएल द्वारा सीएसआर अन्तर्गत जोन्हा, अनगढ़ा ब्लॉक में 9400 स्कावयर फिट में 'कौशल विकास केन्द्र' का निर्माण किया जायेगा। जिसमें आधुनिक सेवाएं सहित बच्चों के आवसीय सुविधा प्रशिक्षण संबंधी समुचित व्यवस्था होगा।

अगले चार सालों में जर्मनी करेगा पर्यावरण पर 54 अरब यूरो खर्च

जर्मनी की सरकार 2023 तक पर्यावरण सुरक्षा पर 54 अरब यूरो खर्च करेगी। मकसद सरकार के पर्यावरण सुरक्षा लक्ष्यों को पूरा करना है. जर्मनी में विशाल रैलियों के बीच पर्यावरण संरक्षकों ने सरकार के कदमों को अपर्याप्त बताया है। जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल ने गठबंधन सरकार के साथियों के साथ पर्यावरण सुरक्षा के कदमों की घोषणा करते हुए कहा कि इन कदमों का मकसद अच्छे इरादे वाले लक्ष्यों को अच्छे इरादे वाले लक्ष्य पूर्ति में बदलना है. इसके पहले चांसलर की सीडीयू समेत सीएसयू और एसपीडी पार्टी के नेताओं ने कई घंटों की बहस के बाद 2030 तक के लिए सरकार के पर्यावरण सुरक्षा कदमों की रूपरेखा तय की।इस 22 पेज वाले दस्तावेज के अनुसार भविष्य में भी क्लाइमेट कैबिनेट काम जारी रखेगा। क्लाइमेट कैबिनेट चांसलर अंगेला मैर्केल के मंत्रिमंडल के खास सदस्यों का दल है जो पर्यावरण पर फैसले लेता है। क्लाइमेट कैबिनेट की सालाना बैठक में इस बात की समीक्षा की जाएगी कि पर्यावरण के लक्ष्यों को पूरा किया जा रहा है या नहीं। यदि उद्योग की कोई शाखा कानूनी लक्ष्यों को पूरा नहीं करती है तो संबंधित मंत्री तीन महीने के अंदर संशोधित कार्यक्रम पेश करेगा ताकि लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में बढ़ा जा सके।1990 के स्तर से 55 फीसदी कटौती का लक्ष्यचांसलर मैर्केल ने कहा कि इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55 फीसदी कम करने का लक्ष्य पूरा हो सके। पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल किए जाने की नियमित समीक्षा के साथ 2021 से परिवहन और मकानों की हीटिंग के क्षेत्र में कार्बन कारोबार शुरु किया जा रहा है।

ऑटोमोबाइल में मंदी की वजह माना जा रहा बीएस-4 और बीएस-6 क्या है

भारत में फिलहाल बीएस-4 मानक उत्सर्जन मानक वाले वाहन चल रहे हैं. अप्रैल, 2020 से आने वाले नए वाहनों में बीएस-6 मानक का पालन किया जाएगा. लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा?भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर बड़ी मंदी की चपेट में है. हर महीने आ रहे आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं. ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों के समूह एसआईएएम(सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफक्चर्स) का कहना है कि जुलाई महीने में वाहनों की बिक्री में 30 प्रतिशत की गिरावट आई है. यही वजह है कि अब कई कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों को कुछ दिनों के लिए बंद कर रही हैं. इन सब की बीच दो शब्द अकसर सुनने को मिल रहे हैं. ये हैं बीएस-4 और बीएस-6. ऑटोमोबाइल उद्योग के जानकार मान रहे हैं कि मंदी के पीछे एक बड़ा कारण अप्रैल, 2020 से लागू हो रहे बीएस 6 एमिसन स्टैंडर्ड भी हैं. लेकिन इसका मतलब क्या है?

क्या है एमिसन स्टैंडर्ड?

एमिसन स्टैंडर्ड का हिंदी में अर्थ है उत्सर्जन मानक. कोई भी ऐसी चीज जो प्रदूषण पैदा करती है, उसके अधिकतम प्रदूषण उत्सर्जन की एक सीमा होती है. इस अधिकतम सीमा का उल्लंघन करने पर उस देश के कानून के मुताबिक सजा हो सकती है. वाहन भी प्रदूषण में अपना योगदान देते हैं. इसलिए इनके लिए भी उत्सर्जन मानक तय किए गए हैं. इन्हें व्हीकल एमिसन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कहा जाता है.

वाहनों में ऊर्जा के लिए इंजन का इस्तेमाल होता है. इन इंजनों में डीजल, पेट्रोल या गैस का इस्तेमाल का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है. इन वाहनों से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) जैसे कारक होते हैं. इसमें ग्रीन हाउस गैसें भी हैं जो जलवायु परिवर्तन की बड़ी वजह हैं. पीएम ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं जो सांस के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं और जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं. ऐसे में इन पर नियंत्रण जरूरी है. 1990 के दशक से पहले वाहनों के लिए इस तरह के मानक नहीं थे. लेकिन जब वाहनों की संख्या और इनसे होने वाले प्रदूषण में बढ़ोत्तरी होने लगी तो इसको नियंत्रित करने के लिए मानक तय किए गए. पश्चिमी देशों और जापान ने सबसे पहले ऐसे मानक बनाए. 1992 में यूरोपियन यूनियन ने यूरो-1 मानक बनाए जो 1993 से लागू किए गए. इसके बाद बने सभी वाहनों से इन्हीं मानकों की सीमा में उत्सर्जन होता था. 1996 में यूरो-2 मानक और 2000 में यूरो-3 मानक लागू हुए. 2005 में यूरो 4, 2009 में यूरो-5 और 2014 में यूरो-6 मानक लागू हुए.

2000 से पहले वाहनों पर भारत में कोई उत्सर्जन मानक लागू नहीं थे. साल 2000 में पूरे भारत में बीएस-1 यानी भारत स्टेज 1 मानक लागू किए गए. ये यूरो-1 मानकों के समान थे. इसके बाद आए मानकों को अलग-अलग स्तरों पर लागू किया गया. बीएस-2 मानक साल 2001 में एनसीआर, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में लागू किया गया. 2003 में इसे 13 शहरों में किया गया. 2005 में इसे पूरे देश में लागू किया गया. इसी साल एनसीआर और 13 शहरों में बीएस-3 लागू कर दिया गया जो 2010 में पूरे देश में लागू हुआ. 2010 में ही एनसीआर और इन 13 शहरों में बीएस 4 लागू कर दिया गया जो 2017 से पूरे भारत में लागू हुए. लागू होने का मतलब जिस तारीख से नए मानक लागू हुए उस दिन के बाद रजिस्टर्ड सभी गाड़ियों को उन मानकों का पालन करना चाहिए. भारत सरकार ने तय किया कि वो बीएस-5 मानक को छोड़कर सीधे बीएस-6 मानक को अपनाएगी. 1 अप्रैल 2020 के बाद भारत में रजिस्टर होने वाले सभी वाहन बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले होने चाहिए.

क्या फर्क है बीएस-4 और बीएस-6 में?

बीएस-6 से सबसे पहला अंतर आता है प्रदूषण में कमी. डीजल और पेट्रोल दोनो में सल्फर होता है. जिस ईंधन में जितना सल्फर ज्यादा होता है उसमें उतनी ज्यादा ताकत और प्रदूषण होता है. डीजल में सल्फर ज्यादा होता है. बीएस-6 वाहनों के उत्सर्जन में सल्फर की मात्रा बीएस-4 की तुलना में पांच गुना तक कम होगी. बीएस-4 में यह मात्रा 50 पार्टिकल पर मिलियन होती है वहीं बीएस-6 में यह 10 पार्टिकल पर मिलियन हो जाएगी. साथ ही नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की मात्रा डीजल वाहनों में 68 प्रतिशत तक और पेट्रोल वाहनों में 25 प्रतिशत तक कम हो जाएगी. इससे ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन होगा.

तकनीक की बात करें तो वाहनों में ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक और रियल ड्राइविंग एमिसन तकनीक लगाई जाएगी. ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक से वाहन के इंजन में किसी भी तरह की परेशानी का संकेत मिलेगा और रियल ड्राइविंग एमिसन से वाहन द्वारा पैदा किए जा रहे उत्सर्जन की उसी समय जानकारी मिल जाएगी. डीजल वाहनों में डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर (डीपीएफ) और सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन (एससीआर) का भी इस्तेमाल किया जाएगा. एससीआर नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को दो अलग-अलग सामान्य उत्पादों नाइट्रोजन और भाप में बदल देगा. इसके लिए डीजल एक्जॉस्ट फ्ल्यूड यानी एडब्ल्यू का इस्तेमाल किया जाएगा. एडब्लू में गैर-आवेशित पानी और यूरिया होता है जो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को विघटित कर देता है. एडब्लू के लिए वाहन में फ्यूल टैंक की तरह एक टैंक लगेगा. इसकी कीमत करीब 127 रुपये लीटर के आसपास है. एक कार में डाला गया 1 लीटर एडब्लू करीब 1200 किलोमीटर चलने तक काम आएगा.

बीएस-6 का असर किस पर क्या होगा

बीएस-6 मानक लागू होने का असर ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ-साथ इसके साथ जुड़े हुए सारे उद्योगों पर पड़ेगा. इसका असर ग्राहकों पर भी पड़ेगा.

ग्राहकों पर इसका पहला असर ये होगा कि वाहनों की कीमत बढ़ जाएगी. साथ ही बीएस-4 की तुलना में वाहन चलाना थोड़ा महंगा हो जाएगा. डीजल वाहनों की कीमतों पर ज्यादा असर होगा. डीजल कारों की कीमत करीब एक से डेढ़ लाख रुपये तक बढ़ जाएगी. पेट्रोल वाहनों की कीमतों में 20 से 50 हजार रुपये का इजाफा होगा. वाहन चलाने की बात करें तो बीएस-6 ईंधन में सल्फर की मात्रा कम होती है. इस वजह से वाहनों की ताकत भी कम हो जाएगी. डीजल वाहनों पर इसका ज्यादा असर दिखेगा.

एक बड़ा असर होगा ईंधन की उपलब्धता का. भारत में अधिकतर पेट्रोल और डीजल पंप बीएस-4 ईंधन बेच रहे हैं. शहरों में बीएस-6 ईंधन की पहुंच आसान होगी. लेकिन गांवों और कस्बों में ऐसा नहीं होगा. इन्हीं इलाकों में भारत की अधिकांश जनसंख्या रहती है. बीएस-6 वाहनों में बीएस-4 ईंधन डालना या बीएस-4 वाहनों में बीएस-6 ईंधन डालना वाहन के इंजन और मालिक की जेब दोनों के लिए ही सही नहीं होगा. क्योंकि बीएस-4 और बीएस-6 ईंधन में सल्फर की मात्रा में बहुत अंतर होगा इससे इंजन को नुकसान करेगा.

ऑटोमोबाइल उद्योग पर असर

वाहन बनाने वाली कंपनियों को अपने वाहनों में अमूलचूल बदलाव करने होंगे. ऑटोमोबाइल उद्योग के जानकारों के मुताबिक उद्योग ने बीएस-5 मानकों को लागू करने के हिसाब से तैयारी कर ली थी. लेकिन सरकार ने बीएस-5 को छोड़कर बीएस-6 लागू करने का फैसला किया. अब बीएस-5 की जगह बीएस-6 वाहन बनाने में समय और पैसा भी लगेगा. सरकार ने 2016 में बीएस-5 को छोड़कर बीएस-6 अपनाने की घोषणा की थी. इससे वाहनों की कीमत भी बढ़ेगी और इस कारण से लोग गाड़ी कम खरीदेंगे.दूसरा बड़ा असर ये है कि सरकार के इस कदम से एक उहापोह की स्थिति पैदा हो गई है. ग्राहकों को शंका है कि कहीं सरकार बीएस-4 वाहनों को पूरी तरह तो बंद नहीं कर देगी. जिससे पुराने बीएस-4 वाहन भी बंद हो जाएंगे. इसलिए वो बीएस-4 वाहन नहीं खरीद रहे. हालांकि सरकार ने यह साफ किया है कि पुराने बीएस-4 वाहन चलते रहेंगे. लेकिन सरकार के पुराने डीजल वाहनों पर लगाए कुछ प्रतिबंध उहापोह की स्थिति को बनाए हुए हैं

जनसंवाद केंद्र में शिकायतों के त्वरित निष्पादन पर कार्यशाला

अधिकारी जागरूक और संवेदनशील बनें: रमाकांत सिंह

रांची:मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष सचिव श्री रमाकांत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को हर स्तर पर जागरूक किया जाना जरूरी है। विभिन्न जिलों में शिकायतों के निष्पादन के बाद उसकी रिपोर्ट जनसंवाद के पोर्टल पर समय पर ऑनलाइन अपलोड की जानी चाहिए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। रमाकांत सिंह शनिवार को सूचना भवन में जनसंवाद केंद्र के विभिन्न जिलों के नोडल पदाधिकारियों की कार्यशाला में बोल रहे थे। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक रामलखन प्रसाद गुप्ता ने नोडल पदाधिकारियों को जनसंवाद में दर्ज होनेवाली शिकायतों के कंप्लायंस एवं उसकी रिपोर्टिंग की बारीकियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनसंवाद का उद्देश्य जनसमस्याओं और जनशिकायतों के ससमय निष्पादन के साथ-साथ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना भी है। जनसंवाद केंद्र के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी डॉ संजय जैन ने जनसंवाद के पोर्टल पर रिपोर्टिंग के तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी दी।

सरायकेला से भी बांस की बनी वस्तुओं को विदेश भेजा जाएगा:- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सरायकेला के नीमडीह स्थित मकुला गांव पहुंचे, आदिम जनजाति की महिलाओं द्वारा बनाये गए बांस की वस्तुओं को सराहा । मध्यम, लघु एवं कुटीर उद्योग गरीबी समाप्त करने में सहायक होगा ।आदिम जनजाति की महिलाओं को नई तकनीक से मिलेगा प्रशिक्षण। 95 हजार शिल्पकार मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड से जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरायकेला/नीमडीह झारखंड को कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड में राज्य के प्रतिभावान शिल्पकारों को चिन्हित कर उनका निबंधन हुआ है। करीब 95 हजार शिल्पकार अब तक बोर्ड से जुड़ चुके हैं। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य शिल्पकारों और कलाकारों को बदलते समय और की मांग के अनुसार प्रशिक्षण देकर उन्हें और प्रतिभावान बनाना है।

......पेज एक का शेष **बीएयू द्वारा विकसित तीसी की दो किस्में**

इसमे पाया जानेवाला लीग्नेन नामक तत्व कैंसर अवरोधी होता है. इन सभी गुणों के कारण विश्व बाजार में तीसी की काफी मांग है।

तीसी की खेती झारखण्ड के किसानों के लिए वरदान

झारखण्ड राज्य की जलवायु और भूमि तेलहनी फसल की खेती के लिए काफी उपयुक्त है. प्रदेश में इसकी उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने की काफी संभावनाएँ मौजूद है. पूरे देश में झारखण्ड राज्य का तिल उत्पादन में छठा स्थान है. वर्ष 2000 में राज्य के करीब 7 हजार हेक्टेयर भूमि में तीसी की खेती होती थी. वर्ष 2017-18 में लगभग 40 हजार हेक्टेयर भूमि में इसकी खेती की गई. अधिक मुनाफा वाली महत्वपूर्ण तेलहनी तीसी फसल राज्य में पुनः प्रचलित हो रही है।पौधा प्रजनक (तीसी) डॉ सोहन राम का कहना है कि प्रदेश में तीसी की परंपरागत खेती से किसानों को कम उत्पादन एवं लाभ मिलता है. राज्य में तीसी फसल की अंतरवर्ती एवं मिश्रित फसल के रूप में गेहूँ ,चना, मसूर, कुसुम, आलू, प्याज, फ्रेंचबीन और ईख फसल के साथ खेती प्रचलित है.

तीसी खेती की लाभप्रद तकनीक

पौधा प्रजनक (तीसी) डॉ सोहन राम बताते है कि राज्य में तीसी खेती का उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर माह तक है. सिंचाई की कमी की अवस्था में धान की खड़ी फसल पकने के समय खेत में तीसी बीज का छिडकाव किया जाता है, जिसे पैरा या उटेरा खेती तकनीक कहते है. यह तकनीक दोन - 1 और दोन - 2 की भूमि में खेती के लिए मुख्य विकल्प है.तीसी की बुआई में कतार की दूरी 30 से.मी. और 20 - 25 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है क असिंचित अवस्था में 40:20:15:15 किलो एनपीके और सल्फर धारी उर्वरक और सिंचित अवस्था में 80:30:20:15 किलो एनपीके और सल्फर धारी उर्वरक की मात्रा अनुशंसित है. बुआई के एक माह बाद इसकी निकाई - गुडाई किया जाना उत्तम रहता है.

इसमें पाई जाने वाली कीट गॉल मिज का उपचार मोनोक्रोटोफॉस तरल (एक लीटर प्रति हे.) तथा उकठा रोग से बचाव के लिए तीसी बीज को 2-3 ग्राम थीरम / 1 ग्राम बेवैस्टीन प्रति किलो बीज से उपचारित कर बुआई करना चाहिए. इसकी खडी फसल में 0.05 प्रतिशत केलिकसींन या 0.10 प्रतिशत बेनोमिल या केलिकसींन + डाईथेन एम 45 (1:1) का 15 दिनों के अंतराल पर मिट्टी को उपचारित कर रोग का नियंत्रण किया जा सकता है.

बीएयू द्वारा विकसित दोनों तीसी किस्मों में तेल की मात्रा ज्यादा और अच्छी उपज राज्य में बीएयू द्वारा विकसित दोनों किस्मों दिव्या (सिंचित) और प्रियम (असिंचित) किस्म की खेती को काफी लाभप्रद पाया गया है.125-130 दिनों में तैयार होने वाली इन दोनों किस्मों में 35 - 41 प्रतिशत तक तेल की मात्रा पाई जाती है. दिव्या और प्रियम की उपज क्षमता 12-16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है. तीसी विशेषज्ञ के अनुसार इन दोनों किस्मों कि अपेक्षा शेखर (सिंचित) किस्म 10-11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज और 30-35 प्रतिशत तक तेल की मात्रा मिलती है.

राज्य में तीसी खेती को बढ़ावा

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आईसीएआर की अखिल भारतीय समन्वित तीसी (अलसी) अनुसंधान परियोजना के तहत जनजातीय बहुल जिलों में वैज्ञानिक प्रबंधन से तीसी (अलसी) की खेती शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है. विगत तीन-चार वर्षो में राज्य के रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला-खरसाँवा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, दुमका एवं साहिबगंज जिले में सैकड़ो से अधिक जनजातीय किसानों के खेतों में जागरूकता अभियान - सह - उन्नत बीज वितरण कार्यक्रम चलाये गये है. इसके तहत वैज्ञानिकों ने किसानों को तीसी खेती की पैकेज प्रणाली, उपयुक्त उन्नत प्रभेद एवं रोग व कीट प्रबंधन की जानकारी दी. उनके बीच मध्यप्रदेश की पीकेडीएल- 41 के साथ बीएयू द्वारा विकसित दिव्या एवं प्रियम उन्नत किस्मों के बीज बांटे गये. विश्वविद्यालय विगत वर्षो में विभिन्न जिलों के जनजातीय किसानों के बीच करीब 450 एकड़ से अधिक भूमि में अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण कराये है और इसके परिणाम बेहद उत्साहजनक रहे है. डॉ आरएस कुरील, कुलपति, बीएयू का कहना है कि बहुअयामी औषधीय गुणों वाली तीसी फसल की देश एवं विदेश में ज्यादा मांग एवं बेहतर मूल्य को देखते हुए तीसी निर्यात की काफी संभावनाए मौजूद है. एक अनुमान के मुताबिक एकफसली धान खेती के प्रचलन से प्रदेश में हर वर्ष धान की खेती उपरांत करीब 14.6 लाख हेक्टेयर भूमि परती पडी रह जाती है. इस वर्ष खरीफ मौसम में वर्षापात की कमी एवं असमान वर्षापात से धान खेत वाली बहुतायत भूमि परती रह जाने से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है. ऐसी परती पड़ी भूमि में कम सिंचाई एवं कम नमी में उगाई जाने वाली तेलहनी फसल तीसी (अलसी) की खेती को अपनाकर किसान अपनी नुकसान की भरपाई सकते हैं. विश्वविद्यालय तीसी अनुसंधान के साथ किसानों के खेतों तक इसके तकनीकी हंस्तातरण में लगातार प्रयासरत है. वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में राज्य के विभिन्न जिलों के सैकड़ो किसान विशेषकर जनजातीय किसानों ने तीसी की खेती को अपनाकर अपनी आय को बढ़ाया है. राज्य के किसानों की आय दुगुनी करने में यह फसल मददगार साबित होगी. राज्य में पोषण सुरक्षा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर तथा किसानों की आय दुगुनी करने में अलसी (तीसी) की खेती एक सशक्त विकल्प साबित हो सकती है।

प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण अनुकूल नहीं: राज्यपाल

माननीया राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सभी नागरिक प्लास्टिक मुक्त भविष्य के निर्माण हेतु अपने–अपने दायित्वों का निर्वहन करें। प्लास्टिक का प्रयोग स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को प्लास्टिक मुक्त करने का आह्वान किया है। समुद्र, नदी–तालाब प्लास्टिक के कारण गंदे एवं दूषित हो रहे हैं। प्लास्टिक का प्रभाव कई सौ साल तक रहता है। राज्यपाल महोदया राज भवन के दरबार हॉल में सिटिजन फाउन्डेशन द्वारा आयोजित “Plastic Free Future Campaign का शुभारंभ कर रही थी।

जलवायु परिवर्तन : पिछले पाँच साल रहे सबसे गर्म साल

मैट मैक्ग्रा

न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की शिखर सम्मेलन से पहले वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि धरती का तापमान घटने की बजाय और तेज़ी से बढ़ रहा है.विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले पाँच साल अब तक रिकॉर्ड में दर्ज सबसे गर्म साल रहे, यानी 2014 से 2019 के बीच रिकॉर्ड गर्मी रही.इसी दौरान कार्बन डाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन में काफ़ी बढ़ोतरी होने के कारण समुद्री जलस्तर में भी वृद्धि हुई.डब्ल्यूएमओ ने बताया कि कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए तत्काल तीव्र प्रयास किए जाने चाहिए.संस्था की रिपोर्ट में बढ़ती गर्मी के प्रभावों और कारणों पर हाल के वर्षों में नवीनतम जानकारियों का एक संकलन पेश किया गया है.इसमें बताया गया है कि 1850 से वैश्विक तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और 2011 और 2015 के बीच 0.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है.ऐसा कार्बन उत्सर्जन बढ़ने से हुआ और 2015 से 2019 के बीच गैस की मात्रा इसके पहले के पांच वर्षों की तुलना में 20 प्रतिशत बढ़ी है.मगर शायद इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा चिंता की बात समुद्री जल स्तर का बढ़ना है.समुद्र के जलस्तर में 1993 से अब तक औसतन 3.2 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही थी. मगर 2014 से 2019 के बीच इसमें प्रति वर्ष पांच मिलीमीटर की वृद्धि हुई. 2007 से 2016 के बीच के दस सालों में हर साल औसतन चार मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है.डब्ल्यूएमओ के महासचिव पेटेरी तालस ने बताया, "समुद्री जलस्तर के बढ़ने में तेज़ी आई है और हम अंटार्टिटक और ग्रीनलैंड बर्फ की परतों के अचानक से पिघलने को लेकर चिंतित हैं, जिससे जलस्तर और बढ़ेगा".शिंजो अबे उन्होंने बताया, "जैसा कि हमने इस साल बहामास और मोज़ाम्बिक में देखा कि कैसे बढ़ते समुद्री जलस्तर और तीव्र उष्णकटिबंधीय तूफ़ानों के कारण मानवीय और आर्थिक तबाही हुई."रिपोर्ट में महासागरों के खतरों का भी उल्लेख है और कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पैदा हुई 90 प्रतिशत से अधिक गर्मी का असर समुद्रों पर पड़ा. डब्ल्यूएमओ के विश्लेषण में कहा गया है कि 2018 में समुद्र का का तापमान सबसे ज़्यादा रहा.रिपोर्ट इस तथ्य को रेखांकित करती है कि अभी धरती पर हर जगह कहानी एक जैसी है. मानवजनित कारणों से धरती का तापमान बढ़ रहा है जिससे गर्मी, लू और जंगलों में आग जैसी घटनाएँ बढ़ रही हैं.ग्रैंथम इंस्टीच्यूट, इम्पीरियल कॉलेज लंदन के अध्यक्ष और रीडिंग विश्वविद्यालय में मौसम विभाग के प्रोफ़ेसर ब्रायन होस्किन्स ने कहा, "हमारी वजह से जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है और ये खतरनाक होता जा रहा है."केवल भाषण नहीं डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष शिखर सम्मेलन को जानकारी देना है.संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के मुताबिक बैठक में कई राजनेता शामिल होंगे, जिसे बयानबाजी नहीं बल्कि कार्रवाई के हिसाब से तैयार किया गया है.संयुक्त राष्ट्रइमेज कॉपीरइटफ्र्ष्वळ्एफ्र उन्होंने बैठक से पहले कहा, "मैंने नेताओं से लच्छेदार भाषण नहीं देने बल्कि ठोस प्रतिबद्धता के साथ आने को कहा है."उन्होंने कहा, "लोग समाधान, प्रतिबद्धता और कार्रवाई चाहते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि एक घोषणा के अलावा अगले दशक के दौरान नाटकीय रूप से उत्सर्जन कम करने के लिए कई उद्देश्यपूर्ण योजनाओं और 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को ख़त्म करने के बारे में कोई घोषणा होगी. सम्मेलन की शुरूआत कुछ युवा कार्यकर्ताओं के भाषण से होगी जिन्होंने पिछले दिनों न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रदर्शन किया था.इसके बाद लगभग 60 राष्ट्राध्यक्षों को अपनी बात कहनी है. चीन, भारत, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन बैठक को संबोधित करेंगे.जापान और ऑस्ट्रेलिया को मंच पर स्थान नहीं दिया गया है.गुटेरेस ने कहा कि जैसा कि 2050 तक जीरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता के लिए देशों को खनिज ईंधनों को कम और कोयले से चलने वाले नए बिजली संयंत्रों का निर्माण बंद करना चाहिए.कोयले के सवाल पर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे और ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन को सम्मेलन से दूर रखा गया है.अमरीका, ब्राज़ील और सऊदी अरब भी इसमें हिस्सा नहीं लेगा.एंटोनियो गुटेरेसइमेज कॉपीरइट विशेष शिखर सम्मेलन कितना कामयाब रहेगा, इसपर संदेह है. मगर इस बात पर किसी को संदेह नहीं कि फ़ौरन कुछ किया जाना चाहिए. और अगर इसमें देरी होती है तो आगे चल कर निर्णय लेना और मुश्किल होगा।

फोटो न्यूज

अमेरिकन माउंट रशमोर फेल है झारखंडी कला के सामने। सिमडेगा जाने के रास्ते में है ये भैरो पहाड़। इसमें आंख नाक मुंह बना कर एक शक्ल दे दिया गया

बांस का सोफा बांस का पलंग :झारखंड की लाजवाब इकोफ्रेंडली कारीगरी

माजूली : जलवायु परिवर्तन ने गृहिणी को मजदूर बना दिया

असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जलवायु परिवर्तन की मार का सबसे बड़ा शिकार है। साल दर साल बदलते मौसम के मिजाज के चलते यह द्वीप लगातार नदी में समा रहा है। अब माजुली द्वीप को बचाने की दिशा में ठोस पहल हो रही है। मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए इसी साल मार्च में इलाके में एक योजना शुरू की है. अब इसी महीने वहां एक कार्बनमुक्त पर्यटन परियोजना भी शुरू की गई है. इसके तहत सैलानियों को साइकिलों के जरिये द्वीप के विभिन्न गांवों में घुमाया जाएगा।

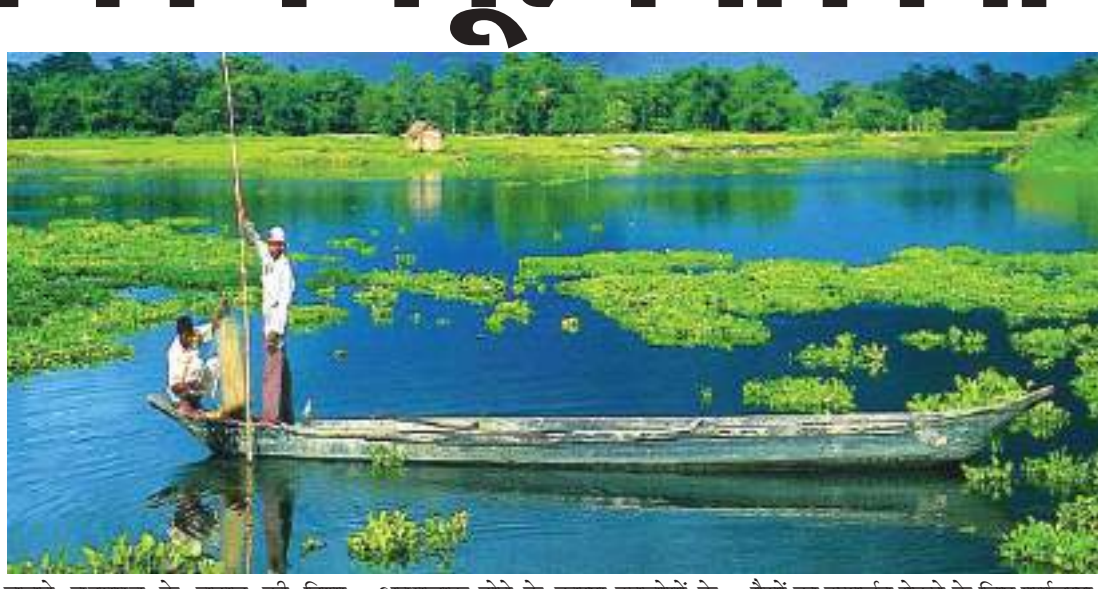

माजुली की विविधता

दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अपने आप में गागर में सागर समेटे है द्वीप के 23 गांवों में कोई 1।68 लाख लोग रहते हैं। यह 15वीं सदी से ही वैष्णव सत्रों या पूजास्थलों का प्रमुख केंद्र रहा है. अब भी यहां 30 ऐसे सत्र हैं। यह सत्र सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र तो हैं ही, छोटे-मोटे विवादों के निपटारे में भी अहम भूमिका निभाते हैं। द्वीप के तमाम गांव अपने-अपने इलाकों में स्थित सत्रों से जुड़े हैं और वहां तमाम धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। माजुली रास उत्सव, टेराकोटा और नदी पर्यटन के लिए भी मशहूर है। लेकिन अपनी स-ांस्कृतक व जैविक विविधताओं वाला यह द्वीप मौसम के लगातार बदलते मिजाज की वजह से अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है.हर साल आने वाली बाढ़ इसका कुछ हिस्सा अपने साथ बहा ले जाती है. वर्ष 1891 में जहां माजुली का कुल क्षेत्रफल 1250 वर्गकिलोमीटर था वहीं अब यह महज 515 वर्गकिलोमीटर रह गया है. बरसों से इसे यूनेस्को के विश्व धरोहरों में शामिल कराने के प्रयास होते रहे हैं। लेकिन अब तक इसमें कामयाबी नहीं मिली है. गैर-सरकारी संगठन माजुली द्वीप सुरक्षा व विकास परिषद का कहना है कि इलाके में तटकटाव की स्थिति इतनी गंभीर है कि अगले 15-20 वर्षों में इस द्वीप के पूरी तरह ब्रह्मपुत्र में समाने का अंदेशा है। बीते एक दशक के दौरान जलवायु परिवर्तन व ग्लोबल वार्मिंग के चलते ब्रह्मपुत्र के बहाव की दिशा बदलने से तटकटाव की दर भी तेज हुई है।

मौसम की मार

सेंटर फॉर एन्वायरनमेंट, सोशल एंड पालिसी रिसर्च (सीईएसपीआर) ने इंडियन नेटवर्क ऑन एथिक्स एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिल कर किये गये एक साझा अध्ययन में कहा है कि जलवायु में होने वाले बदलावों से असम में बाढ़ व कटाव की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है और उसकी वजह से राज्य में लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है. इस अध्ययन में राज्य के जिन छह जिलों को शामिल किया गया था उनमें माजुली भी है. सीईएसपीआर की प्रवक्ता सविता देवी कहती हैं, "माजुली की महिलाएं पहले महज गृहिणी की भूमिका में थीं। लेकिन अब वह घरों से निकल कर बुनाई या मजदूरी करने पर मजबूर हैं ताकि प-रवार की रोजी-रोटी चल सके." वह कहती हैं कि बाढ़ में खेतों के बह जाने या रेत की परत की वजह से उनके अनुपजाऊ होने के कारण उनलोगों के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है.असम कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केके सहारिया कहते हैं, "जलवायु परिवर्तन का आकलन महज खेती और अर्थव्यवस्था के विकास, धर्म, परंपराओं, जीवन व आजीविका, सामाजिक संक्रमण और ऐसे ही कुछ अन्य मुद्दों के संदर्भ में ही नहीं किया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों की जीवन प्रणाली पर मंडराते खतरे और उनके आसपास की तेजी से बदलती दुनिया के साथ सामंजस्य के पैमाने पर भी इसका आकलन किया जाना चाहिए।

अब बीते साल माजुली से चुनाव लड़ने वाले मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल की जीत के बाद केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों ने इस द्वीप की समस्याओं पर ध्यान देने की शुरुआत की है. सबसे पहले तो इसे जोरहाट से अलग कर अलग जिले का दर्जा दिया गया। उसके बाद इस साल मार्च में सरकार ने द्वीप पर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन रोकने के लिए पर्यावरण सम्मत विकास की योजना शुरू की है. ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने की योजना फ्रांस की विकास एजेंसी की सहायता से असम के जंगल और जैविक-विविधता के संरक्षण के लिए चलाई जा रही परियोजना का हिस्सा है।मुख्यमंत्री सोनोवाल कहते हैं, "इस योजना का मकसद माजुली में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश लगा कर वर्ष 2020 तक इसे देश का पहला कार्बनमुक्त जिला बनाना है." इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया है।सरकार ने माजुली में एक कार्बनमुक्त पर्यटन योजना भी शुरू की है। इस माजुली सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मकसद इस द्वीप पर कार्बममुक्त पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस-के तहत यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को साइकिल से द्वीप के विभिन्न गावों में घूमने को लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उनको यह साइकिलें किराए पर दी जाएंगी। इस योजना में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने की भी योजना है. पर्यावरणविदों का कहना है कि महज इन योजनाओं को शुरू कर देने भर से काम नहीं चलेगा। इनको लंबे अरसे तक लगातार जमीनी स्तर पर लागू करने से ही इसके सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे।

वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ

राजीव गुप्ता

चालीस साल पहले, मैं जब एक फार्म में रहता था, तो देखता था कि सभी किसानों के खेतों में कुछ पेड़ जरूर होते थे। ये किसान के लिये एक तरह से बीमे जैसा था। यह संस्कृति खास तौर पर कर्नाटक में थी कि उन पेड़ों को वे अपने बेटों, बेटियों के नाम दे देते थे। जब एक बेटी के विवाह का अवसर आता था तो वे एक पेड़ काट डालते और उससे सारा खर्च निकल जाता था। अगर बेटे को उच्च शिक्षा के लिये यूनिवर्सिटी जाना होता तो एक और पेड़ से उसका भी खर्च निकल आता। खेतों पर हमेशा पेड़ होते ही थे। लेकिन 40 साल पहले रासायनिक खादों की कंपनियों ने भारत के गांवों में ऐसा प्रचार करना शुरू किया कि अगर आप खेतों पर पेड़ रखेंगे तो उनकी जड़ें सब खाद खा जाएंगी और फसल कमजोर होगी। तो उन्होंने किसानों को पेड़ काट डालने के लिये तैयार किया। ये सोच कर कि रासायनिक खादें पेड़ों पर व्यर्थ हो जाएंगी, हमने लाखों पेड़ काट दिए। आज परिस्थिति ये हो गयी है कि हमारा पानी का प्रत्येक श्रोत- चाहे जमीन के नीचे का पानी हो या नदियों का- कम हो रहा है। उसका कारण ये है कि भले ही पिछले 100 सालों से, सारे उपमहाद्वीप में, बरसात लगभग एक जैसी ही हो रही है, पर पेड़ों के न रहने से जमीन के अंदर पानी को रोक कर रखने की हमारी क्षमता समाप्त हो गयी है। जब बरसात होती है तो पानी रुकता नहीं, बह जाता है और बाढ़ आ जाती है। और फिर जब बरसात खत्म हो जाती है तो सूखा पड़ जाता है। यदि आप आज के जल संकट के बारे में विचार करें तो 1947 में, देश में प्रति व्यक्ति जितना पानी था, आज उसका 25% ही उपलब्ध है। यह प्रगति नहीं है। यह तो कोई विकास नहीं है। तमिलनाडु के कई शहरों में बहुत समय से ऐसा हो रहा है कि लोग तीन दिनों में एक ही बार नहाते हैं। तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सारा पानी बह कर तेजी से नदियों में न पहुंच जाए। यह करने का एक ही रास्ता है कि हमारी जमीन पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ हों। यह कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है। यह मेरा मुख्य उदेश्य हो गया है। मैं सारे विश्व को, संयुक्त राष्ट्र संघ को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को यही कह रहा हूं।

अम्बेडकर रीजेंट ऑक्सफोर्ड स्कूल में दो दिवसीय स्वच्छता अभियान मनाया गया

रांची: 25सितंबर को मोती राज सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में धुर्वा स्थित अम्बेडकर रीजेंट ऑक्सफोर्ड स्कूल में दो दिवसीय स्वच्छता अभियान मनाया गया। विप छात्र नेता आशुतोष द्विवेदी ने विद्यर्थियों को स्वच्छता की शपत दिलाई। साथ ही साथ विद्यर्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस अभियान को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बच्चों ने विद्यालय परिसर की सफाई ,खेल मैदान की सफ़ाई, सड़क की सफ़ाई, आदि किया। कार्यक्रम में स्कूल की निदेशिका संगीता कुमारी,प्रचार्य अमित कुमार,प्रशांत आनंद साही कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राए उपस्थित थे। ये जानकारी साजन ने दी।

बाजार में कपड़े का थैला बांटते हैं सुरेन्द्र

प्लास्टिक एवं पॉलिथीन से होने वाले नुकसान को देखते हुए रायपुर के एक परिवार ने प्लास्टिक के खिलाफ जंग छेड़ी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहने वाले सुरेंद्र बैरागी और उनके परिवार ने शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए एक नेक पहल की शुरुआत की है। सुरेंद्र की पत्नी आशा पुराने कपड़े, चादर या फिर अनुपयोगी कपड़ों से थैला सिलने का कार्य करती हैं, वही सुरेंद्र अपने मित्रों और बच्चों के साथ इन थैलों को बाज़ार में बाँट देते हैं।अपने परिवार के सदस्य और मित्रों के साथ वह हर शाम बाज़ार जाते हैं और कपड़े के थैले बांटते हैं। साथ ही लोगों से पॉलिथिन का उपयोग बंद करने के लिए निवेदन भी करते हैं।

जंगली हाथियों से सुरक्षा के सामान्य उपाये

झारखण्ड में हाथी दुमका, दलमा, पलामू, सारण्डा आदि के घने जंगलों में हमेशा देखे जाते हैं एवं भ्रमण के दौरान राज्य के अनेक जिलों में देखा जा सकता है। जब तक हाथियों को तंग नहीं किया जाता है तो साधरणतः अपने रास्ते पर खाते-पीते हुए झारखण्ड के कई शहरों एवं गांवों में घुस आते हैं जिसके कारण इनका टकराव मनुष्यों से हो रहा है और जान-माल की क्षति हो रही है।

हाथियों से बचने के लिए क्या करें?

1.हाथियों को देखने के के लिये पास न जायें एवं उनका रास्ता न रोकें और भीड़ जमा न होने दें।

2. हाथियों को लगातार न खदेड़ें एवं जंगल में उनका पीछा ना करें

3. जंगल में लगे क्षेत्र में खलिहान ना बनायें एवं खलिहानों में रात को ना सोयें।

4. अगर हाथियों द्वारा संग्रहित अनाज खाया जाता है तो उनको ना छेड़ें। इसके नुकसान का मुआवजा वन विभाग द्वारा दिया जाता है।

5.हाथी शराब की ओर आकर्षित होते हैं अतः जब क्षेत्र में हाथी रहें, तब तक हड़िया या देशी शराब ना बनायें।

6.बिजली वाले गावों के घरों एवं खंभों पर तेज रोशनी वाले बल्ब लगायें।

7.हाथियों के सूंघने की शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है। अतः भागने के क्रम में हवा की दिशा का ध्यान रखें। एवं हवा की दिशा में यदि हाथी हो तो मिर्च का मशाल बना कर धुंआ करें।

8. हाथी आने की सूचना तत्काल निकटवर्ती वन विभाग के कर्मचारियों को दें।

9. यदि हाथी से सामना हो जाय तो तुरन्त उसके लिए रास्ता छोड़ें। पह-ाड़ी स्थानों में सामना होने पर दूर रहे ओर आपको सुरक्षित स्थान पर पहुँचने का मौका मिल जाय।

10. लाल मिर्च के पाउडर को जले हुए मोबिल अथवा ग्रीस में अच्छी तरह मिलाकर उसे मोटी रस्सी में लपेटें। रस्सी को भंडारित अनाज वाले घर के चारों ओर लपेट कर अथवा हाथी के गांव में प्रवेश की दिशा में बांधें। रस्सी के साथ श्वेत या लाल कपड़े की पट्टी भी बाँधकर लटका दें, क्योंकि हाथी इन रंगों को नापसंद करते हैं। इस प्रक्रिया के 25 से 30 दिनों के अन्दर पुनः दूसरा लेप चुण्ड को भगाने का प्रयास न करें, उसे थोड़ा समय दें।

11. हाथियों को भगाने के क्रम में श्वेत वस्त्रा या लाल वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह रंग उन्हें चिड़चिड़ा बनाता है।

12. हाथी को देखकर पूजा या प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके नजदीक न जायें।

13.संरक्षित वन्यप्राणी ;संरक्षण अधिनयम, 1972 के तहत अनुसूची-1 में हाथी को संरक्षण प्राप्त है। इसे किसी तरह का नुकसान पहुँचाना कानूनन जुर्म है। झारखण्ड में राजकीय पशु के रूप में सम्मान प्राप्त है। इनकी रक्षा एवं संरक्षण करना हमारा कर्त्तव्य है। हाथियों में भी भावना होती है एवं कापफी संवेदनशील होते हैं। हाथी मनुष्य द्वारा उत्तेजित करने पर चिड़चिड़ा एवं क्रोध्ति हो उठते हैं एवं आक्रमण कर बैठते हैं, अतः हमें इनकी भावनाओं का ध्यान रखकर इनके संरक्षण में सहयोग करना है। हाथियों के टकराव से बचने के लिए हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, की जानकारी अतिआवश्यक है। सावधनीपूर्वक इन बातों का पालन करने से हाथियों से टकराव की सम्भावना घटायी जा सकती है।

सीसीएल ने की कांके डैम से कचड़े की सफाई

रांची: भारत सरकार की मुहिम 'स्वच्छता ही सेवा' के अंतर्गत सीसीएल मुख्यालय की टीम ने रांची नगर निगम के सहयोग से रांची के कांके डैम जलाशय के आसपास के इलाके को प्लास्टिक मुक्त करने हेतु स्वच्छता अभियान चलाया । सीसीएल कर्मियों एवं सफाई कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत और प्रयास के बाद लगभग एक टन कचड़ा जमा किया। इस अवसर पर सीएसआर विभाग के अधिकारियों द्वारा आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट के दुष्प्रभाव के बारे में अवगत कराया और उन्हें जागरूक किया।

अटल स्मृति वेंडर मार्केट'' रांची नगर निगम, रांची में झारखंड फिल्म थियेटर अकादमी के कलाकारों ने ''नुक्कड़ नाटक'' प्रस्तुत किया गया जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट के विभिन्न नकारात्मक पहूलओं पर प्रकाश डाल कर आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया गया। सीसीएल अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को भारत सरकार की मुहिम प्लास्टिक वेस्ट मुक्त भारत के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हम छोटे-छोटे उपायों को अपनाकर इस महान कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन महाप्रबंधक ए.के. सिंह, मुख्य प्रबंधक रत्नेश श्रीवास्तव, के.ए. सुन्दर, मुख्य प्रबंधक रवि प्रकाश, सहायक प्रबंधक श्रीमती निकिता भदानी, प्रवीण कुमार तथा सीएसआर की टीम के सक्रिय सहयोग से किया जा रहा है।

बांस की खेती हेतु अनुदान

राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत गैर वन भूमि् रैयती भूमि पर बांस की खेती करने के लिये योग्य उद्यमियों को अनुदान प्रदान किया जायेगा। छोटी नर्सरी के लिये सांकेतिक इकाई दस लाख रूपये का पचास प्रतिशत अनुदान एवं ब्लॉक प्लांटेशन के लिये एक लाख रूपया प्रति हेक्टेयर का पचास प्रतिशत अनुदान राशि दी जायेगी। निजी उद्यमियो द्वारा स्थापित क्ये जाने वाले उद्योगों को क्लस्टर के रूप में दूमका एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों तथा निकटवर्ती क्षेत्र में स्थापित किया जाना है। आवेदक का निबंधन उद्योग विभाग, झारखंड सरकार के तहत अनिवार्य है।परियोजना प्रस्ताव संबंधित जिले के वन प्रमंडल पदाधिकारी , विश्व खाद कार्यक्रम प्रमंडल के कार्यालय में समर्पित होगा। परियोजना प्रस्ताव की सॉफ्ट कॉपी सीधे मुख्य वन संरक्षक- सह- मुख्य समन्वयक विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखंड, रांची-सह मिशन निदेशक, झारखंड बांस विकास अभिकरण, झारखंड, रांची के कार्यालय को ईमेल : ccf-wfpranchi@gov.in पर भेजी जायेगी।

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः मनोज कुमार शर्मा* (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN00962, email:greenrevolt2019@gmail.com. Ph. 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।